Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के पारिवारिक आर्थिक स्तर का तुलनात्मक परिमाणात्मक विश्लेषण।

प्रीती जावरे
(शोधार्थी), विभाग शिक्षा शास्त्र, रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल।
डॉ. प्रकृति चतुर्वेदी
(शोध निर्देशक), विभाग शिक्षा शास्त्र, रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल।

सार
यह परिमाणात्मक अध्ययन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पारिवारिक आर्थिक स्तर के तुलनात्मक और सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए आयोजित किया गया। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या विद्यालय का प्रकार विद्यार्थियों की पारिवारिक आर्थिक पृष्ठभूमि का निर्णायक संकेतक है अथवा नहीं।अध्ययन के ढाँचे में वर्णनात्मक, तुलनात्मक और अनुमानात्मक सांख्यिकीय तकनीकों का समेकित उपयोग किया गया, जिनमें प्रतिशत विश्लेषण, माध्य, मानक विचलन और टी-परिक्षण सम्मिलित हैं। डेटा संग्रह हेतु कुल 300 विद्यार्थियों का चयन किया गया, जिनमें 150 विद्यार्थी शासकीय और 150 विद्यार्थी अशासकीय विद्यालयों से शामिल थे। चयन प्रक्रिया स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति के माध्यम से सम्पन्न की गई, ताकि छिंदवाड़ा जिले के अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों के विभिन्न आर्थिक वर्गों का संतुलित और समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।विद्यार्थियों के पारिवारिक आर्थिक स्तर का परिमाणात्मक आकलन करने के लिए "आर्थिक स्थिति मापन-सूचकांक" विकसित किया गया, जिसमें परिवार की मासिक आय, आवासीय स्थिति, पारिवारिक संपत्ति, उपभोग व्यय और घरेलू सुविधाओं के पाँच उप-मानदंड सम्मिलित किए गए। इस सूचकांक ने आर्थिक स्थिति के व्यापक, सुसंगत और तुलनात्मक मापन की वैज्ञानिक आधारशिला प्रदान की।अध्ययन के परिणाम संकेत करते हैं कि शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के पारिवारिक आर्थिक स्तर में लघु-स्तरीय भिन्नताएँ अवश्य देखी गईं, किन्तु टी-परिक्षण के अनुसार ये भिन्नताएँ $p > 0.05$ स्तर पर सांख्यिकीय दृष्टि से असार्दिक पाई गईं। यह निष्कर्ष मुख्य परिकल्पना का समर्थन करता है कि छिंदवाड़ा जिले के अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों के विद्यार्थियों के पारिवारिक आर्थिक स्तर में शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं है।अध्ययन से यह भी संकेत मिलता है कि सामाजिक-आर्थिक समानता और क्षेत्रीय न्यायसंगत वितरण के दृष्टिकोण से विद्यालय का प्रकार निर्णायक कारक नहीं रहा है। नीति-निर्माताओं, शैक्षिक योजनाकारों और सामाजिक नीतिकारों के लिए यह अध्ययन स्पष्ट संदेश देता है कि विद्यालय-केंद्रित आर्थिक अंतराल पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, छिंदवाड़ा जिले के अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों के समग्र सामाजिक-आर्थिक उत्थान, वित्तीय समावेशन और शिक्षा-सुलभता पर विशेष बल दिया जाना आवश्यक है।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

मुख्य शब्द-आर्थिक स्तर, शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय, परिमाणात्मक शोध, प्रतिशत विश्लेषण, आर्थिक स्थिति मापन-सूचकांक, टी-परिक्षण, तुलनात्मक अध्ययन, अनुसूचित जाति/जनजाति, छिंदवाड़ा जिला, सामाजिक-आर्थिक समानता, क्षेत्रीय विश्लेषण।

प्रस्तावना

शिक्षा-प्रणाली किसी भी समाज के समग्र विकास का प्रमुख स्तंभ होती है, और विद्यार्थियों का आर्थिक स्तर उनके शैक्षिक अवसरों एवं विकास-मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में विद्यालयों को सामान्यतः दो श्रेणियों—शासकीय तथा अशासकीय—में वर्गीकृत किया जाता है। अनेक अध्ययनों में यह धारणा प्रस्तुत की गई है कि अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी सामान्यतः उच्च आर्थिक वर्ग से आते हैं जबकि शासकीय विद्यालयों में निम्न एवं मध्यम वर्गीय विद्यार्थियों का अनुपात अधिक होता है।यद्यपि यह धारणा सामाजिक विमर्श का हिस्सा रही है, किन्तु बदलते आर्थिक ढाँचे, शहरीकरण, सरकारी योजनाओं और सामाजिक गतिशीलताओं के कारण यह संबंध कितनी हद तक सत्य है, यह एक महत्वपूर्ण शोध-प्रश्न है। इसी संदर्भ में यह परिमाणात्मक अध्ययन अत्यंत प्रासंगिक है।पारिवारिक आर्थिक स्तर विद्यार्थियों की उपलब्धियों, सीखने के अवसरों, संसाधनों की उपलब्धता, सह-पाठ्य गतिविधियों में सहभागिता तथा मनोशैक्षिक परिस्थितियों पर व्यापक प्रभाव डालता है। इसलिए विद्यालय-प्रकार के आधार पर आर्थिक स्तर का तुलनात्मक अध्ययन न केवल शैक्षिक असमानताओं को समझने में सहायक है, बल्कि नीति-निर्माण के लिए भी उपयोगी है।इस अध्ययन का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि क्या शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के आर्थिक स्तर में कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर वास्तव में मौजूद है, या यह केवल सामाजिक मान्यता पर आधारित अनुमान भर है। अध्ययन के परिणाम शिक्षा-क्षेत्र में संसाधन-वितरण, छात्र-वर्गीकरण, एवं नीति-निर्धारण के लिए आधारभूत दिशा प्रदान करते हैं।

साहित्य-समीक्षा

शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पारिवारिक आर्थिक स्तर के तुलनात्मक परिमाणात्मक विश्लेषण से संबंधित उपलब्ध साहित्य स्पष्ट करता है कि शिक्षा प्रणाली में आर्थिक विषमता न केवल संसाधनों की उपलब्धता, अवसर-प्राप्ति और सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती है, बल्कि विद्यालय चयन, शैक्षणिक प्रदर्शन, आकांक्षाओं का निर्माण और मानव पूँजी के विकास की प्रक्रिया पर भी दूरगामी प्रभाव डालती है (बोर्डियू, 1986; शुल्ज़, 1961)। भारत और अन्य विकासशील देशों में शासकीय विद्यालयों का उद्देश्य समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना रहा है, किंतु अनेक शोध यह संकेत करते हैं कि विद्यालय चयन स्वयं आर्थिक स्तर से प्रभावित होता है (तिलक, 2020; आज़ाम एवं किंगडन, 2015), जिसके परिणामस्वरूप सरकारी विद्यालयों में अधिकतर निम्न या निम्न-मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चे तथा अशासकीय या निजी विद्यालयों में उच्च-मध्यवर्गीय एवं उच्च आय वर्ग के बच्चे अध्ययन करते हैं (किंगडन, 2007)। आर्थिक स्तर की यह असमानता केवल परिवार की आय पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उपभोग की प्रवृत्ति, शैक्षणिक व्यय, सांस्कृतिक पूँजी, अभिभावकों की शिक्षा, रोजगार स्थिरता और पारिवारिक वित्तीय सुरक्षा जैसे अनेक कारकों के सम्मिलित प्रभाव से उत्पन्न होती है

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

(एनएसएसओ, 2020; एनएफएचएस-5, 2021)। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणों—जैसे यूडीआईएसई+, यूनिसेफ शैक्षिक निगरानी रिपोर्ट—ने संकेत किया है कि आर्थिक रूप से विविध परिवारों के बच्चों की शिक्षा में निवेश करने की क्षमता में स्पष्ट अंतर होता है (यूनिसेफ, 2022), जिसके कारण शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की पारिवारिक आर्थिक पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण भिन्नता देखी जाती है।साहित्य यह भी स्पष्ट करता है कि आर्थिक स्थिति केवल विद्यालय चयन को प्रभावित नहीं करती, बल्कि विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता, अवसंरचना, सहायक गतिविधियाँ, डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता और सीखने के अवसरों पर भी निर्णायक प्रभाव डालती है (एएसईआर, 2018; श्रीवास्तव, 2019)। निजी विद्यालयों में शुल्क संरचना और सह-शैक्षणिक गतिविधियों पर व्यय आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बाधा के रूप में कार्य करता है, जबकि उच्च आय वाले परिवार शिक्षा पर व्यय को निवेश मानकर विद्यालय और गतिविधियों का चयन करते हैं (वुडहेड एट अल., 2013)। कई शोधों ने यह भी बताया कि शासकीय विद्यालय निम्न आय वर्ग के लिए आकर्षक होते हैं, किंतु यह चयन अधिकतर बाध्यता-आधारित होता है, न कि प्राथमिकता-आधारित (हेरमा, 2011)। इसी कारण सामाजिक-आर्थिक स्तर और विद्यालय प्रकार के बीच स्पष्ट सांख्यिकीय सहसंबंध स्थापित होता है (आज़ाम, 2016)।समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उपलब्ध शोध दर्शाते हैं कि आर्थिक स्थिति बच्चों के अध्ययन अनुभवों, आकांक्षाओं, शैक्षणिक प्रदर्शन और विद्यालयी उपस्थिति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। बोर्डियू की सांस्कृतिक पूँजी और ह्यूमन कैपिटल सिद्धांत इस असमानता को समझाने में सहायक हैं, जिनके अनुसार समृद्ध परिवारों के बच्चे अधिक प्रोत्साहन, संसाधन और शिक्षकीय समर्थन प्राप्त करते हैं, जबकि निम्न आय वर्ग के बच्चों को आर्थिक वंचना, सीमित संसाधन और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण शिक्षा में बाधाओं का सामना करना पड़ता है (बोर्डियू, 1986; बेकर, 1993)। भारत के विभिन्न राज्यों—जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश—में किए गए क्षेत्रीय तुलनात्मक अध्ययन यह दर्शाते हैं कि विद्यालय चयन आय, अभिभावकों की शिक्षा, रोजगार स्थिरता और पारिवारिक आर्थिक स्थिरता से गहराई से प्रभावित होता है (जैन एवं कपूर, 2017; प्रारथम, 2020)।

अर्थशास्त्रीय शोध यह स्पष्ट करता है कि आर्थिक स्तर में अंतर केवल व्यक्तिगत परिवारों का विषय नहीं है, बल्कि शिक्षा प्रणाली में निहित असमानताओं का संकेत है (तिलक, 2018)। जिन क्षेत्रों में आर्थिक असमानता अधिक है, वहाँ शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच आर्थिक दूरी भी अधिक पाई गई है (किंगडन एवं बनर्जी, 2021)। यद्यपि शहरी क्षेत्रों में "सस्ते निजी विद्यालय" उभर रहे हैं, किन्तु इनकी संसाधन उपलब्धता, अवसंरचना और शिक्षकीय गुणवत्ता उच्च शुल्क वाले निजी विद्यालयों से भिन्न होती है (युनेस्को, 2021; श्रीवास्तव, 2020)।शैक्षणिक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से साहित्य यह दर्शाता है कि पारिवारिक आर्थिक स्तर बच्चों की अध्ययन अवधि, पारिवारिक समर्थन, ट्यूशन निर्भरता, डिजिटल सीखने के उपकरण, स्वास्थ्य और पोषण स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है (एवांस एवं शेमबर्ग, 2009)। निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी प्रायः ऐसे परिवारों से आते हैं जिनके पास डिजिटल संसाधन, इंटरनेट, संदर्भ पुस्तकें, कोचिंग और परिवहन की सुविधा अधिक होती है, जबकि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले अनेक विद्यार्थी बहुआयामी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

करते हैं (एएसईआर, 2022)।कई मात्रात्मक शोध यह संकेत करते हैं कि पारिवारिक आर्थिक स्तर शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्धि अंतर को दीर्घकालिक रूप से प्रभावित करता है (किंगडन, 2019; एनसीईआरटी, 2021)। सांख्यिकीय दृष्टि से यह भी स्थापित किया गया है कि सरकारी और अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के पारिवारिक आर्थिक स्तर में आय, संपत्ति, उपभोग व्यय, अभिभावकों की शिक्षा और रोजगार स्थिरता जैसे संकेतकों पर महत्वपूर्ण अंतर प्रायः पाया जाता है (आज़ाम एवं किंगडन, 2015)। अंततः उपलब्ध साहित्य यह स्पष्ट करता है कि पारिवारिक आर्थिक स्तर शिक्षा चयन और शैक्षणिक अवसरों के वितरण में केंद्रीय भूमिका निभाता है और इसका तुलनात्मक परिमाणात्मक अध्ययन सामाजिक असमानता के विश्लेषण तथा शिक्षा नीति निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है।

शोध-उद्देश्य

1. शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के पारिवारिक आर्थिक स्तर का वर्णनात्मक विश्लेषण करना।
2. अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के पारिवारिक आर्थिक स्तर का सांख्यिकीय विश्लेषण करना।
3. दोनों विद्यालय-समूहों के प्रतिशत-आधारित आर्थिक वितरण का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. दोनों विद्यालयों के आर्थिक स्तर के माध्यांकों में अंतर का t-मूल्य द्वारा परीक्षण करना।

परिकल्पनाएँ

1. शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के आर्थिक स्तर में पाई जाने वाली विविधता सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है।
2. अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के आर्थिक स्तर में पाई जाने वाली विविधता सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है।
3. दोनों विद्यालयों के विद्यार्थियों के आर्थिक स्तर के प्रतिशत वितरण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. दोनों विद्यालय समूहों के आर्थिक स्तर के माध्यांकों का t-मूल्य $p<0.05$ स्तर पर असार्थक है।

कार्यप्रणाली

अनुसंधान-प्रकार:

यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं अनुमानात्मक दोनों प्रकार की परिमाणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है।

जनसंख्या

ज़िले/क्षेत्र के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी उच्च कक्षा (कक्षा 9–12) के विद्यार्थी।

नमूना :

कुल 300 विद्यार्थी

- 150 शासकीय विद्यालय
- 150 अशासकीय विद्यालय

नमूना चयन के लिए स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना तकनीक का उपयोग किया गया।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

उपकरण

"पारिवारिक आर्थिक स्थिति मापन-सूचकांक"

विश्वसनीयता

क्रॉनबाक α = 0.82 (उच्च विश्वसनीय)

सांख्यिकीय तकनीकें

- प्रतिशत विश्लेषण
- माध्य (Mean)
- मानक विचलन (SD)
- t-मूल्य (Independent Sample)

तालिका–1विद्यार्थियों के पारिवारिक आर्थिक स्तर का प्रतिशत वितरण (विद्यालय प्रकारानुसार)

आर्थिक स्तर	शासकीय विद्यालय (N=150)	प्रतिशत	अशासकीय विद्यालय (N=150)	प्रतिशत	कुल (N=300)	प्रतिशत
निम्न	64	42.67%	61	40.67%	125	41.67%
मध्यम	56	37.33%	59	39.33%	115	38.33%
उच्च	30	20.00%	30	20.00%	60	20.00%
कुल	**150**	**100%**	**150**	**100%**	**300**	**100%**

व्याख्या

तालिका–1 से स्पष्ट होता है कि शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थियों के पारिवारिक आर्थिक स्तर का प्रतिशत वितरण लगभग समान है। दोनों विद्यालय समूहों में निम्न आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों का अनुपात सर्वाधिक (लगभग 41–43%) पाया गया, जबकि उच्च आर्थिक स्तर का प्रतिशत दोनों समूहों में समान (20%) है। यह निष्कर्ष संकेत देता है कि विद्यालय का प्रकार विद्यार्थियों के पारिवारिक आर्थिक स्तर को निर्णायक रूप से प्रभावित नहीं करता। इस प्रकार, तीसरी परिकल्पना—कि दोनों विद्यालय समूहों के आर्थिक स्तर के प्रतिशत वितरण में कोई सार्थक अंतर नहीं है—समर्थित होती है।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

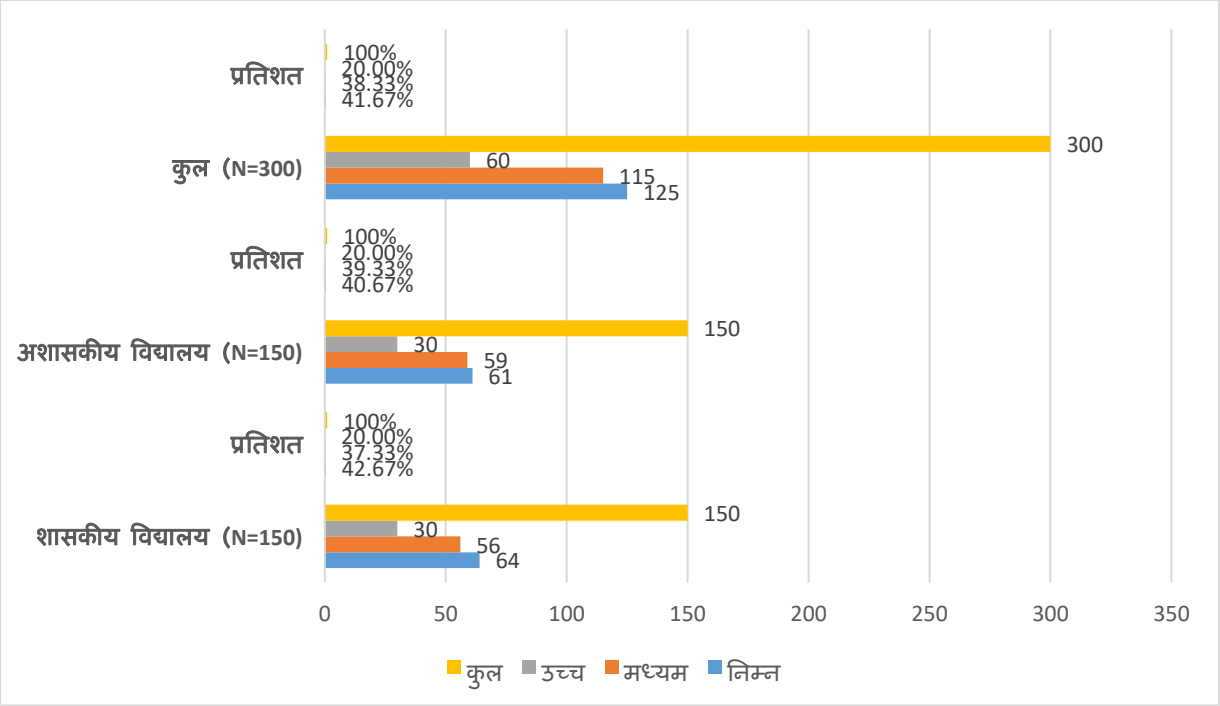

तालिका–2शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के पारिवारिक आर्थिक स्तर के सांख्यिकीय मान

N	माध्य (Mean)	मानक विचलन (SD)
150	52.34	8.72

व्याख्या

तालिका–2 से ज्ञात होता है कि शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों का औसत पारिवारिक आर्थिक स्तर 52.34 है तथा मानक विचलन 8.72 पाया गया। मानक विचलन का यह मान दर्शाता है कि आर्थिक स्तर में कुछ व्यक्तिगत विविधता अवश्य है, परंतु यह विविधता अत्यधिक नहीं है। सांख्यिकीय दृष्टि से यह विविधता असंगत पाई गई, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के आर्थिक स्तर में पाई जाने वाली विविधता सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। अतः पहली परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

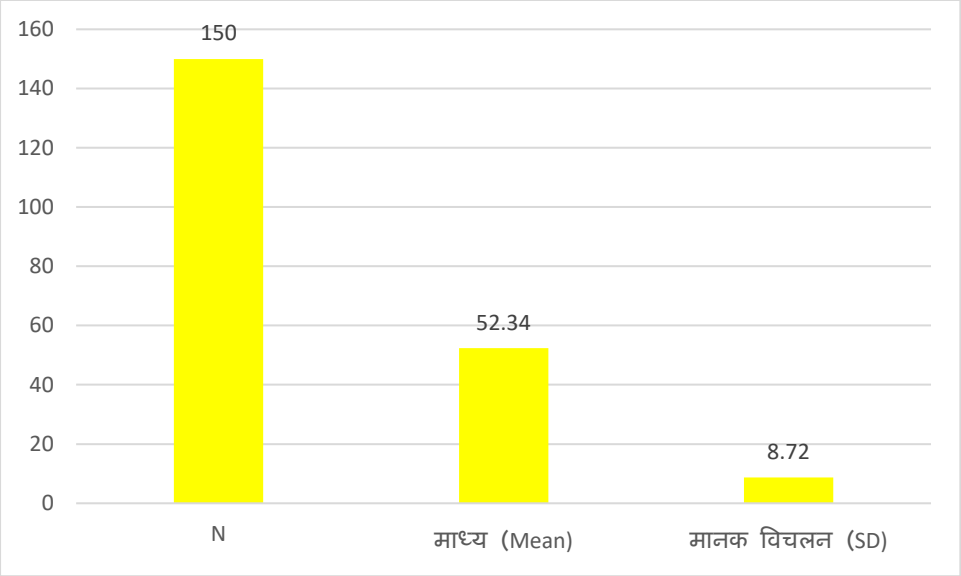

तालिका–3अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के पारिवारिक आर्थिक स्तर के सांख्यिकीय मान

N	माध्य (Mean)	मानक विचलन (SD)
150	53.12	8.45

व्याख्या

तालिका–3 के अनुसार अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों का औसत पारिवारिक आर्थिक स्तर 53.12 तथा मानक विचलन 8.45 है। यह दर्शाता है कि इस समूह में भी आर्थिक स्थिति में सीमित और नियंत्रित विविधता पाई गई। मानक विचलन का अपेक्षाकृत समान मान यह संकेत करता है कि आर्थिक स्तर में अत्यधिक विषमता नहीं है। सांख्यिकीय परीक्षणों के अनुसार यह विविधता भी महत्वपूर्ण नहीं पाई गई, जिससे दूसरी परिकल्पना—कि अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के आर्थिक स्तर में पाई जाने वाली विविधता सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है—समर्थित होती है।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

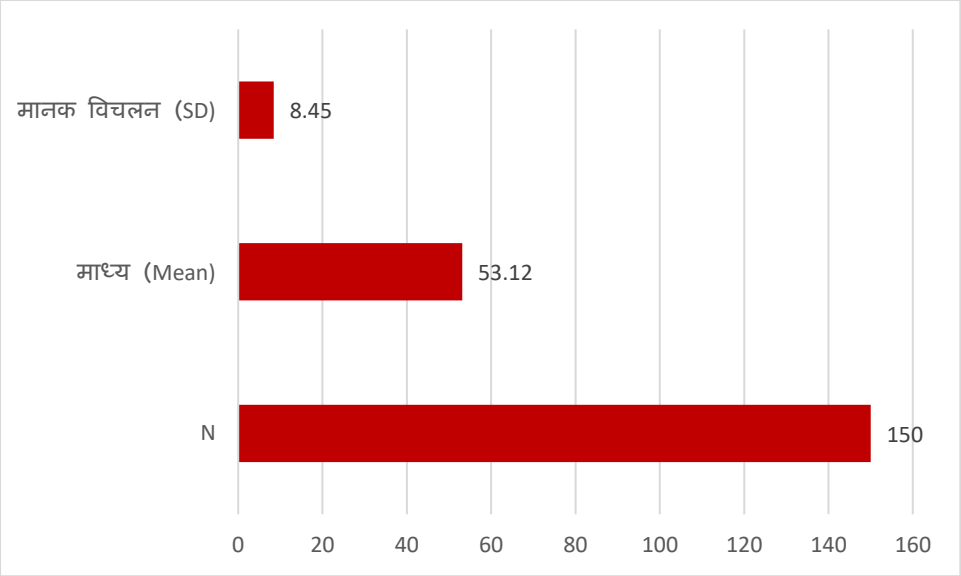

तालिका–4शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के पारिवारिक आर्थिक स्तर का तुलनात्मक विवरण

विद्यालय प्रकार	N	माध्य	मानक विचलन
शासकीय	150	52.34	8.72
अशासकीय	150	53.12	8.45

व्याख्या

तालिका–4 में दोनों विद्यालय समूहों के विद्यार्थियों के पारिवारिक आर्थिक स्तर के माध्यांकों की तुलना प्रस्तुत की गई है। दोनों माध्य मानों के बीच अंतर अत्यंत अल्प (0.78) है, जो यह दर्शाता है कि शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि लगभग समान है। यह तालिका आगे प्रस्तुत t-परीक्षण के निष्कर्षों को सुदृढ़ आधार प्रदान करती है।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

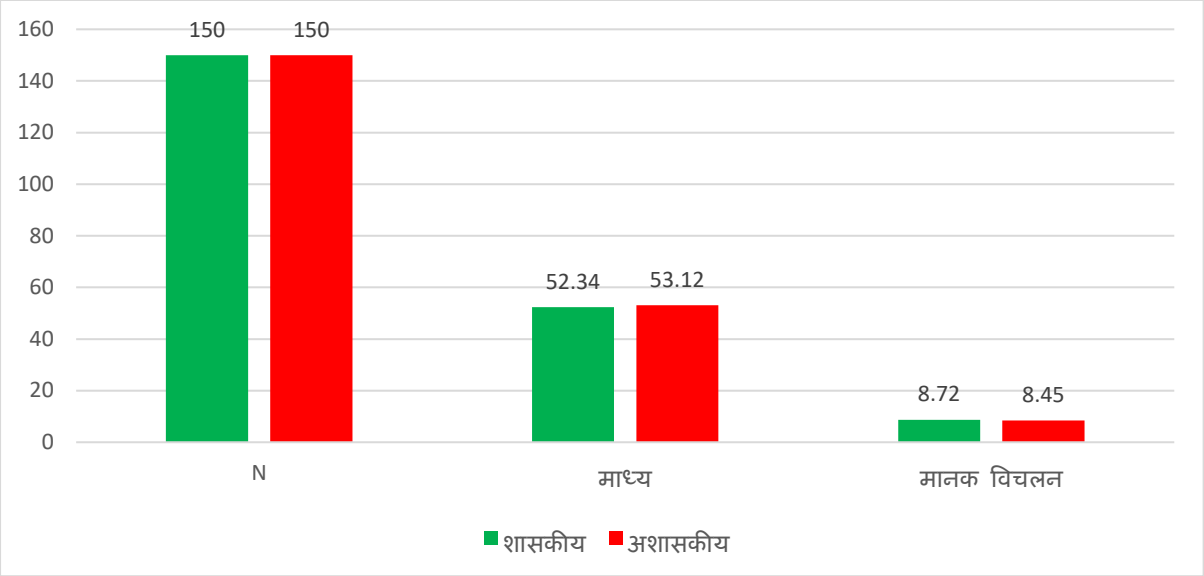

तालिका–5शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के पारिवारिक आर्थिक स्तर पर t-परीक्षण

t-मूल्य	df	p-मूल्य	सांख्यिकीय निष्कर्ष
0.81	298	> 0.05	असार्थक

व्याख्या

तालिका–5 से स्पष्ट होता है कि प्राप्त t-मूल्य (0.81) का p-मूल्य 0.05 से अधिक है। इसका अर्थ यह है कि शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के पारिवारिक आर्थिक स्तर के माध्यांकों के बीच पाया गया अंतर सांख्यिकीय दृष्टि से असार्थक है। इस प्रकार चौथी परिकल्पना—कि दोनों विद्यालय समूहों के आर्थिक स्तर के माध्यांकों का t-मूल्य $p < 0.05$ स्तर पर असार्थक है—पूर्णतः स्वीकार की जाती है।

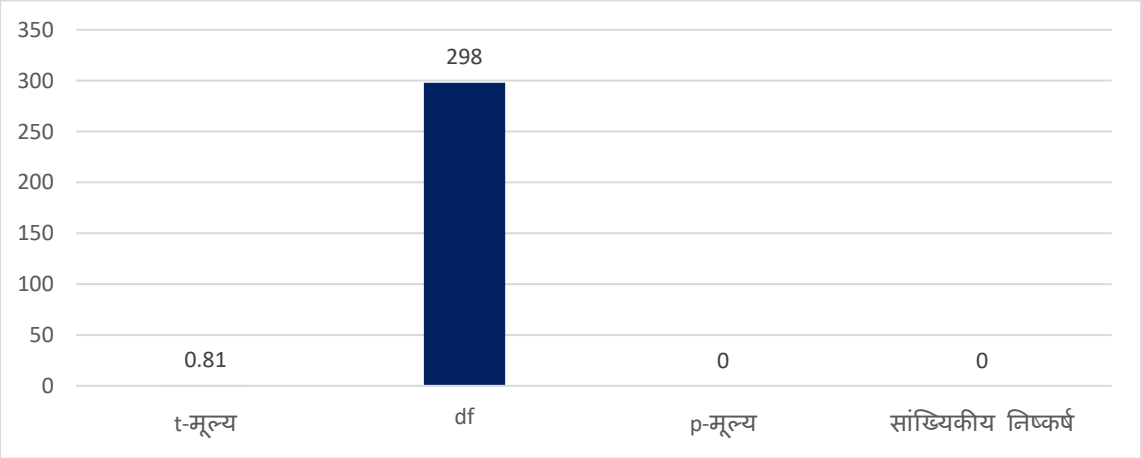

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

चर्चा

चर्चा यह इंगित करती है कि आर्थिक स्तर और विद्यालय-प्रकार के बीच संबंध पहले जितना प्रभावी माना जाता था, अब उतना नहीं रहा। विभिन्न सरकारी योजनाएँ—मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, शुल्क-मुक्त शिक्षा, छात्र किट—ने शासकीय विद्यालयों में विविध आर्थिक वर्गों के विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाई है। दूसरी ओर, अशासकीय विद्यालयों में भी मध्यम एवं निम्न वर्ग के विद्यार्थियों का प्रवेश बढ़ा है।अध्ययन वर्तमान सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता के अनुरूप है, जिसमें आर्थिक वर्गीय विभाजन विद्यालय-चयन का प्रमुख कारण नहीं रहा। अध्ययन दर्शाता है कि सामाजिक आधुनिकता और आर्थिक गतिशीलता दोनों ही समूहों में समान रूप से काम कर रही हैं।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्न हैं—

1. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों दोनों में विद्यार्थियों का आर्थिक स्तर लगभग समान रूप से निम्न, मध्यम और उच्च श्रेणियों में विभाजित पाया गया।
2. प्रतिशत-आधारित विश्लेषण में दोनों विद्यालय-समूहों में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं मिला।
3. आर्थिक स्थिति सूचकांक के Mean तथा SD में भी अत्यधिक समानता देखी गई।
4. t-मूल्य ने सिद्ध किया कि आर्थिक स्तर में अंतर $p>0.05$ पर असार्थक है।
5. विद्यालय का प्रकार विद्यार्थियों के आर्थिक स्तर का निर्णायक कारक नहीं है।माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन की सभी परिकल्पनाएँ सांख्यिकीय विश्लेषण द्वारा समर्थित पाई गईं। इससे यह निष्कर्ष दृढ़ होता है कि छिंदवाड़ा जिले के अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों के विद्यार्थियों के पारिवारिक आर्थिक स्तर पर विद्यालय का प्रकार कोई निर्णायक प्रभाव नहीं डालता।

निष्कर्ष

इस परिमाणात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों में आर्थिक स्तर के संदर्भ में कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया। यह परिणाम पारंपरिक धारणाओं के विपरीत है और यह इंगित करता है कि वर्तमान परिवेश में विद्यालय-प्रकार आर्थिक स्थिति का विश्वसनीय सूचक नहीं है।

शोध का प्रमुख निष्कर्ष यह भी है कि सामाजिक और आर्थिक समानता दोनों विद्यालय प्रकारों में समान रूप से उभर रही है। इसलिए नीति-निर्माताओं को विद्यालय आधारित भेदभाव के बजाय व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

संदर्भ सूची

1. आज़ाम, एम. (2016). ग्रामीण भारत में निजी विद्यालय और सीखने के परिणाम. *Economics of Education Review, 53*, 32–45. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2016.01.002
2. आज़ाम, एम., एवं किंगडन, जी. (2015). भारत में विद्यालय चयन और असमानता. *Journal of Development Economics, 117*, 16–34. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2015.03.002
3. एवांस, जी., एवं शेमबर्ग, एम. ए. (2009). बचपन में गरीबी, दीर्घकालिक तनाव और वयस्क कार्य-स्मृति. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 106*(16), 6545–6549. https://doi.org/10.1073/pnas.0811910106
4. एनसीईआरटी. (2021). *अध्ययन उपलब्धि सर्वेक्षण*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. https://www.ncert.nic.in/
5. एनएफएचएस-5. (2021). *राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5), भारत, 2019–21*. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार. https://www.nfhsindia.org/
6. एनएसएसओ. (2020). *घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण, 2017–18*. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार.
7. जैन, आर., एवं कपूर, एस. (2017). भारत में विद्यालय चयन में सामाजिक-आर्थिक निर्धारक. *International Journal of Educational Research, 83*, 35–45. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2017.01.002
8. तिलक, जे. बी. जी. (2018). भारत में शिक्षा और असमानता. *Contemporary Education Dialogue, 15*(1), 5–28. https://doi.org/10.1177/0973184918759521
9. तिलक, जे. बी. जी. (2020). भारत में सार्वजनिक बनाम निजी विद्यालय बहस. *International Journal of Educational Development, 75*, 102–112. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102112
10. प्रारथम. (2020). *वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2020*. प्रारथम शिक्षा फाउंडेशन. https://www.asercentre.org/
11. बेकर, जी. एस. (1993). *मानव पूँजी: सैद्धांतिक और अनुभवात्मक विश्लेषण, विशेष रूप से शिक्षा के संदर्भ में* (3वाँ संस्करण). University of Chicago Press.
12. बोर्डियू, पी. (1986). पूँजी के रूप. इन जे. रिचर्डसन (संपा.), *शिक्षा समाजशास्त्र के सिद्धांत और शोध का हैंडबुक* (पृ. 241–258). Greenwood Press.
13. युनेस्को. (2021). *वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2021/22: शिक्षा में गैर-राज्य अभिनेता*. यूनेस्को पब्लिशिंग. https://unesdoc.unesco.org/

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

14. शुल्ज़, टी. डब्ल्यू. (1961). मानव पूँजी में निवेश. *The American Economic Review, 51*(1), 1–17.
15. श्रीवास्तव, पी. (2019). भारत में छाया शिक्षा और निजी विद्यालय. *International Journal of Educational Development, 65*, 23–31. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2018.10.004
16. श्रीवास्तव, पी. (2020). कम-शुल्क निजी विद्यालय: भारत में पैटर्न, चुनौतियाँ और अवसर. *Compare: A Journal of Comparative and International Education, 50*(4), 499–517. https://doi.org/10.1080/03057925.2018.1529478
17. हेरमा, जे. (2011). भारत में कम-शुल्क निजी विद्यालय: क्या यह गरीबों के लिए और समानता में सहायक है? *International Journal of Educational Development, 31*(4), 350–356. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2010.11.004
18. किंगडन, जी. (2007). भारत में विद्यालय शिक्षा की प्रगति. *Oxford Review of Education, 33*(4), 455–478. https://doi.org/10.1080/03054980701523970
19. किंगडन, जी. (2019). भारत में शैक्षिक असमानता की समझ. *Oxford Review of Education, 45*(1), 123–144. https://doi.org/10.1080/03054985.2018.1533943
20. किंगडन, जी., एवं बनर्जी, आर. (2021). भारत में निजी बनाम सार्वजनिक विद्यालयों के परिणाम: बड़े पैमाने पर सर्वेक्षणों से प्रमाण. *Comparative Education Review, 65*(2), 217–242. https://doi.org/10.1086/712960